



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102023-249250
CG-DL-E-07102023-249250

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4206]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 7, 2023/ आश्विन 15, 1945

No. 4206]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7, 2023/ASVINA 15, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4377(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 5 अक्टूबर, 2023 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4348(अ), जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) तारीख 5 अक्टूबर, 2023 को प्रकाशित की गई थी, द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) को विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि, उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन उपरोक्त विधि-विरुद्ध संगम से सम्बन्धित, उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा भी किया जाएगा।

[फा. सं. 14017/13/2023—एनआई—एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2023

S.O. 4377(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government has declared the Jammu and Kashmir Democratic Freedom Party (JKDFP), to be an unlawful association under the said Act *vide* notification number S.O. 4348(E) dated the 5th October, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 5th October, 2023.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby directs that all powers exercisable by it under section 7 and section 8 of the said Act shall also be exercised by the State Governments and the Union territory administration in relation to the above said unlawful association.

[F. No.14017/13/2023-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.